जनसत्ता

नए रिश्तों का दौर

अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत-सम्मान में आयोजित भव्य समारोह 'हाउडी मोदी' का संदेश साफ है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में अब नए युग की शुरुआत हैं। इस आयोजन की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं मानी जानी चाहिए कि यह भारतीयों और अमेरिकियों की ओर से मोदी का सम्मान भर था, बल्कि यह समारोह इस वजह से ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसमें मौजूद रहे, मंच से हर मामले में मोदी की तारीफ की। आतंकवाद से निपटने से लेकर कारोबारी रिश्तों तक को मजबूत करने में अमेरिका भारत के साथ एकजुट दिखा। क्या कोई सोच सकता है कि आयात शुल्क जैसे मुद्दे पर कभी भारत को धमकाने वाले ट्रंप इस तरह दिल खोल कर भारतीय प्रधानमंत्री की आवभगत करेंगे! यह कोई मामूली बात नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, टेक्सास के गवर्नर सहित तमाम बड़ी हस्तियां और कारोबारियों के साथ पचास हजार लोग स्टेडियम में मौजूद रहे। मोदी के इस सम्मान से वैश्विक पटल पर एक बार फिर भारत का डंका बजा है। हालांकि पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह के आयोजनों में प्रवासी नागरिकों का दिल जीता है। 24 सितंबर 2014 को भी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर मोदी ने बीस हजार भारतीयों को संबोधित किया था।

ह्यूस्टन का समारोह जहां अमेरिका के साथ रिश्तों के नए आयाम गढ़ने वाला रहा है, वहीं इस मंच से ट्रंप और मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का जो संकल्प व्यक्त किया है, वह पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए स्पष्ट और कड़ा संदेश है। दोनों नेताओं ने अपने भाषण में आतंकवाद को लेकर जो कुछ कहा, उसका सार यही था कि इस्लामी आतंकवाद दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा है और इससे मिल कर निपटना होगा। इसके मायने पाकिस्तान को समझने चाहिए। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने पिछले कुछ समय में जिस तरह से भारत का साथ दिया है, उससे भी पाकिस्तान सकते में है। राष्ट्र हितों को लेकर ट्रंप और मोदी के बीच वैचारिक साम्यता की एक और झलक हाउडी मोदी में देखने को मिली। जहां भारत में घुसपैठियों को खदेड़ने के खिलाफ सरकार ने ठान रखी है, वहीं मैक्सिको से आने वाले लोगों के लिए ट्रंप का रुख भी दुनिया के सामने है। अवैध नागरिकों का मुद्दा भी इस समारोह से दूर नहीं रह पाया। स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोग 'जयश्री राम' और 'राम लला हम आएंगे .. मंदिर वहीं बनाएंगे' जैसे नारे लगा रहे थे। जाहिर है, भविष्य के भारत को लेकर मोदी की नीतियों और उनके काम को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को भी उनसे उम्मीदें काफी हैं।

प्रधानमंत्री का ह्यूस्टन दौरा भारतीयों से मुलाकात और कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने के मकसद से ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहा है। अमेरिकी तेल कंपनियों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक भारत के ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित रही और कई बड़े फैसले हुए। इससे अब भारत के ऊर्जा बाजार में निवेश बढ़ाने के लिए अमेरिकी कंपनियों को और आसानी होगी। भारत की तात्कालिक चिंता कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर है, क्योंकि सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमले के बाद से तेल उत्पादन पर भारी असर पड़ा है। ऐसे में अब अमेरिका भारत को कच्चा तेल देगा। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। कारोबारी लिहाज से अमेरिका अब भारत की अहमियत अच्छी तरह समझ चुका है। भारत के लिए यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है।

ताक पर कानून

पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें लोगों ने किसी व्यक्ति पर आरोप लगा कर कानून अपने हाथ में ले लिया और पीट-पीट कर उसकी जान ले ली। यह प्रवृत्ति चिंताजनक रूप से बढ़ी है और अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। रविवार को आई खबरों के मुताबिक देश के अलग-अलग हिस्सों में सिर्फ शक के आधार पर तीन लोगों की बुरी तरह पिटाई गई जिससे उनकी मौत हो गई। दिल्ली में लोगों के घरों में खाना बना कर गुजारा करने और अपने बच्चों को पढ़ाने वाली एक विधवा महिला को चोरी का आरोप लगा कर एक परिवार ने इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई। इसी तरह, राजस्थान के झालावाड़ जिले में चोर बता कर एक दलित युवक को बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। इसके अलावा, झारखंड में गोमांस बेचने के आरोप में तीन युवकों की बुरी तरह पिटाई की गई, जिसमें एक की मौत हो गई। कानून की फिक्र को ताक पर रख एक दिन में इस तरह की तीन घटनाएं आखिर क्या बताती हैं? क्या स्थिति यहां तक आ चुकी है कि भीड़ में शामिल होने या किसी बहाने जानलेवा तरीके से पिटाई करने वाले लोगों के दिमाग में कानून का खयाल नहीं आता?

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में कानून नहीं बन सकता है और लोकतंत्र में भीड़तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अदालत ने भीड़ के हाथों हत्या को एक अलग अपराध की श्रेणी में रखने और इसकी रोकथाम के लिए नया कानून बनाने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद मौजूदा कानूनों को भी धता बता कर ऐसी घटनाएं जिस तरह बदस्तूर जारी हैं, उससे साफ है कि ऐसे अपराधों पर लगाम लगाना शायद सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है। कभी गोमांस के बहाने तो कभी बच्चा चोरी या फिर कोई सामान चुराने के आरोप में पकड़े गए किसी व्यक्ति को जब कोई समूह बर्बरता से पिटाई करने लगता है तो आखिर उसका विवेक क्यों ऐसा करने की इजाजत देता है? ऐसे लोगों को यह समझना जरूरी क्यों नहीं लगता कि अगर कोई काम कानून की परिभाषा में अपराध है तो उसके लिए सजा भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तय होगी? ऐसे लोग आरोपी को पकड़ने के बाद उसे पुलिस के हाथों में क्यों नहीं सौंपते और उनकी जानलेवा पिटाई की हिम्मत उनके भीतर कहां से आती है?

हालांकि किसी अफवाह या आरोप की वजह से लोग जिस तरह एक भीड़ की शक्ल में तब्दील हो रहे हैं, उसकी स्वाभाविक परिणति यही है कि ऐसी स्थिति में किसी तथ्य पर विचार करना जरूरी नहीं समझा जाता है और दिमाग पर सिर्फ उत्तेजना और उन्माद हावी रहता है। इसके अलावा, जो लोग भीड़ बन कर हिंसा करते हैं, अक्सर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती, संदेह या भ्रम के आधार पर ज्यादातर लोग हत्या के अपराध से बच जाते हैं या फिर कई बार उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे भी मामले सामने आए जब भीड़ के हाथों हत्या के अभियुक्तों को जमानत मिली तो किसी बड़े नेता ने उनका स्वागत भी किया। सवाल है कि क्या इससे बाकी जगहों पर अराजक तत्त्वों को शह नहीं मिलेगी? उन्माद की मानसिकता में जीने वाली भीड़ किसी के नियंत्रण में नहीं रहती है और उसका खमियाजा अमूमन निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर यह चलन इसी रफ्तार से आगे बढ़ी तो देश के लोकतांत्रिक ढांचे और विधि के शासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी।

कल्पमेधा

जिस समय हम समझते हैं कि नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय अक्सर हम दूसरे के नेतृत्व में होते हैं।

– बायरन

जाली मुद्रा का बाजार

अभिजीत मोहन

नोटबंदी से पहले देश के विभिन्न बैंकों के एटीएम से नकली नोट निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई बैंकों के चेस्ट में भारी मात्रा में नकली नोट पाए गए थे। यह किसी से छिपा नहीं है कि देश में ऐसे कई गिरोह हैं जो नकली नोटों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वे जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं।

यह चिंताजनक है कि सरकर की कड़ी निगरानी के बावजूद देश में नकली नोटों का प्रवाह थम नहीं पा रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक बीते दो वर्षों में नकली नोटों की संख्या में दस गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 और 2018-19 में नकली नोटों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। चिंता की बात यह है कि बड़े नकली नोटों के अलावा अब दस, बीस और पचास रुपए के छोटे नकली नोट भी बाजार में हैं। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि एक वर्ष के दौरान दस, बीस और पचास रुपए के नकली नोटों में क्रमशः 20.2, 87.2 और 57.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यानी दो साल के दरम्यान छोटी मुद्राओं में नकली नोटों की संख्या चार गुना तक बढ़ी है। आंकड़ों पर गौर करें तो पचास रुपए के नकली नोटों की संख्या नौ हजार से बढ़ कर छत्तीस हजार तक पहुंच गई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बाजार में सबसे अधिक सौ रुपए के नकली नोट मौजूद हैं। हालांकि सौ रुपए के नकली नोटों में साढ़े फीसद की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो वर्षों में दो हजार रुपए के नकली नोटों की संख्या में भी बाईस प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसी तरह दो सौ रुपए के नकली नोटों में एक सौ साठ गुना वृद्धि हुई है।

पिछले साल 2018 में दो सौ रुपए के उनयासी जाली नोट पकड़े गए थे, जबकि इस साल इनकी संख्या बारह हजार सात सौ अट्ठासी हो गयी। इसी तरह पांच सौ रुपए के नकली नोटों में एक सौ इक्कीस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। 2016-17 में पांच सौ रुपए के नकली नोटों की संख्या सिर्फ एक सौ निन्यानवे थी, जो 2018-19 में बढ़ कर बाईस हजार पहुंच गई। गत वर्ष एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि पिछले दस सालों में देश के बैंकिंग तंत्र में लेनदेन के दौरान नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले तेजी से बढ़े हैं। साल 2007-08 में सरकार ने पहली बार यह अनिवार्य किया था कि निजी बैंकों और देश में संचालित सभी विदेशी बैंकों के लिए नकली मुद्रा पकड़े जाने संबंधी किसी भी घटना की जानकारी धनशोधन रोधी कानून के प्रावधान के तहत वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को देनी होगी। उसके बाद से एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009-10 में सवा लाख से से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज हुए थे। एक ही साल यानी 2010-11 में ऐसे दर्ज मामलों की संख्या ढाई लाख से ज्यादा हो गई और वर्ष 2011-12 में ये सवाल तीन लाख से ऊपर निकल गए। इन आंकड़ों से साफ है कि देश में बड़े पैमाने पर नकली नोटों का प्रवाह जारी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो भी खुलासा कर चुका है कि देश में सबसे अधिक पांच सौ रुपए के नकली नोट चल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2015 में पांच सौ रुपए के 2,99,524 नोट, सौ रुपए के 2,17,189 नोट और एक हजार रुपए के 1,78,022 नकली नोट बरामद किए गए। नोटबंदी से पहले के एक आंकड़े के मुताबिक रिजर्व बैंक और जांच एजेंसियों की संख्ती के बावजूद भारतीय बाजार में मौजूद साढ़े ग्यारह लाख करोड़ रुपए की मुद्रा में बड़ी संख्या में नकली नोट मौजूद होने का खुलासा हुआ था। यह भी आशंका जाहिर की गई थी कि यह आंकड़ा चार सौ करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकता है। नोटबंदी से पहले देश के विभिन्न बैंकों के एटीएम से नकली नोट निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई बैंकों के चेस्ट में भारी मात्रा में नकली नोट पाए गए थे। यह किसी से छिपा नहीं है कि देश में ऐसे कई गिरोह हैं जो नकली नोटों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन वे जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर हैं। अब भी पाकिस्तान नकली नोटों की खेप बांग्लादेश के जरिए भारत में भेज रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पहले भी खुलासा कर चुकी हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ सालाना दस हजार करोड़ रुपए मूल्य के भारतीय नोटों की नकली मुद्रा छाप कर भारत में भेजने की योजना पर काम कर रही है। खास बात यह कि नोटबंदी के बाद भी पाकिस्तान इस खेल में जुटा हुआ है।

दरअसल, उसकी मंशा नकली नोटों के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारतीय

अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की है। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2010 में तकरीबन सोलह अरब रुपए मूल्य की नकली मुद्रा नेपाल और बांग्लादेश के जरिए भारत भेजी गई थी। इसी तरह वर्ष 2011 में बीस अरब रुपए की नकली मुद्रा भेजी गई। इस जाली मुद्रा में तकरीबन साठ फीसद हिस्सा पाकिस्तान में छापा गया था। वर्ष 2015 में भी इन रास्तों से तकरीबन तीन करोड़ से ज्यादा की मुद्रा पकड़ी गई थी।

अच्छी बात है कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के नागरिकों को प्रचार-प्रसार के जरिए असली-नकली नोटों के फर्क को समझाता रहता है। बैंकों को भी हिदायत दी जाती है कि वे नोटों को लेने से पहले उसकी जांच जरूर कर लें। इसमें दो राय नहीं कि नोटबंदी के बाद भी नकली मुद्रा के धंधे से जुड़े लोगों पर अभी तक पूरी तरह से शिकंजा नहीं कसा जा सका है। हालांकि भारत सरकार ने नकली नोटों पर अंकुश रखने के उपाय सुझाने के लिए शैलभद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट पर अमल करते हुए मुद्रा निदेशालय में अतिरिक्त सचिव स्तर का महानिदेशक का पद सृजित किया गया है। इसके अलावा कई अन्य और कदम उठाए गए हैं। मसलन, सरकार ने बेहद सुरक्षित किस्म के कागजों पर नोट छापने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैसूर में अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित नोटों के कागज बनाने का कारखाना लगाया जा रहा है। इस कारखाने में निर्मित करेंसी कागज की नकल करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। गौरतलब है कि अभी भारत में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश करेंसी कागज आयातित होते हैं। हर वर्ष भारत तेरह अरब रुपए मूल्य के कागज आयात करता है।

नकली नोटों के अवैध धंधे को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र और राज्य सरकारों की सुरक्षा व खुफिया एजेंसियां मिल कर काम कर रही हैं। गौरतलब है कि एजेंसियों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय में एक संयोजन समिति बनाई गई है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल एक तरफ बिना छपाई वर्ष वाले 2005 से पुराने नोटों को परिचालन से बाहर कर दिया है। वहीं नए नोटों पर सुरक्षा मानक ज्यादा उन्नत बना दिए गए हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने पिछले साल से ही नंबर पैनल पर आकार में नोटों के नंबर की छपाई बढ़ते हुए क्रम में शुरू कर दी है। बेहतर होगा कि भारत सरकार नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए और कड़ा कदम उठाए। इसमें अमेरिका मददगार साबित हो सकता है। इसलिए कि उसके पास नकली नोटों से निपटने की उच्च प्रौद्योगिकी विद्यमान है और साथ ही उसके पास हर नकली अमेरिकी डॉलर का फोटो सहित डाटाबेस भी उपलब्ध है। उसे जानकारी हो जाती है कि नकली डॉलर कहां और किस रास्ते से आता है और इसे लाने वाले लोग कौन लोग हैं। अगर भारत भी अमेरिकी प्रौद्योगिकी की सहायता लेता है तो निःसंदेह नकली नोटों से निपटने में मदद मिलेगी।

नसीहत के फूल

राजेंद्र प्रसाद

हरेक की जिंदगी के समंदर में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं। ऐसे में जब कभी एकांत में जिंदगी के बारे में सोचने-विचारने का अवसर मिलता है तब समझ आता है कि केवल सांस लेने या छोड़ने का नाम जिंदगी नहीं है। ऐसी स्वतः स्फूर्त क्रिया तो निहायत कुदरती उसूल है, जिसे हमें याद नहीं करना पड़ता कि सांस कब लेना या कब छोड़ना है। अगर हम ठीक से जीवन पर विचार करें तो बहुत सारे पहलू और आयाम हमसे जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा पैदा होने के बाद ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है त्यों-त्यों खुद को संसार में मोह-माया की केंचुली में निरंतर ऐसा लिपटा हुआ पाता है, जिसमें अपने इर्द-गिर्द के परिवार वाले या संसारवासी समझा-पढ़ा देते हैं कि पढ़ो, पैसा कमाओ और विकास की भूख को शांत करो। इससे ऐसा जरूर लगता है जैसे बचपन में हम खूब पढ़ें, बड़े होकर अच्छा भविष्य बनाएं। अच्छा भविष्य पैसा कमाने से जुड़ा हुआ देखते हैं या गृहस्थी चलाने के लिए अर्थ को प्रधान मान कर विकास की सब क्रियाओं से गुजरते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अर्थ के चक्कर में बहुत सारा अनर्थ भी जीवन में कर जाते हैं, जिसकी आपाधापी में इंसान का जीवन कीचड़ में ऐसा सन जाता है कि जीवन का उद्देश्य बहुत सीमित-सा जान पड़ता है।

यों देखें तो जीवन में दुनिया की अच्छी-बुरी बातें कही-सुनी और की जाती है, सिर्फ अमल करना बाकी रह जाता है। सांसारिक चक्र से थोड़ा-सा सोचें तो लगेगा कि जिंदगी के असली और प्राकृतिक आनंद से हम अपने को काफी जुदा पाते हैं। मोटे तौर पर चार तरह के लोग होते हैं- पहले, जो जल्दी से कोई गलती नहीं करते या ठोकर खाने से पहले ही संभले होते हैं; दूसरे, किसी को ठोकर खाकर देखते हुए देख संभल जाते हैं; तीसरे, खुद ठोकर खाकर भविष्य के लिए संभल जाते हैं और चौथे, वे जो ठोकर खाकर भी कभी नहीं संभलते।

दुनिया मेरे आगे

बेशक जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत जानते हैं। कटु सत्य है कि गलत को गलत और सही को सही पहचानना और कहना आज के युग में असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। लगता है कि हम बदलते दौर के ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जहां लोग साधारण नहीं, असाधारण से हो गए हैं। सामाजिक नहीं, कुछ असामाजिक हो रहे हैं और इंसानियत को भूल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब गलत हैं। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा पद्धति, समाज और परिवारों के सोचने और काम करने का ढंग भी दोषी है। इसलिए संवाद का स्थान विवाद और समाधान का स्थान समस्या ले रही है।

जीवन में जीने के मकसद पर विचार करने की आदत होनी चाहिए। कुछ लोग तो यह भी कह गए हैं- 'न चादर बड़ी कीजिए, न ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए।' जीवन को सही और सार्थक बनाने के लिए अगर हम सीखना चाहें तो संसार में सीखने-करने की बहुत सारी चीजें हैं। उनमें महत्त्वपूर्ण है- नसीहतें, जो चिंतकों-विचारकों और महान लोगों के अनुभवों के खजाने से निकली हैं। नसीहतें हमारे जीवन के अंधकार को हटा कर रोशनी करती हैं, सबक लेने का मौका देती हैं और जीवन के रूप-स्वरूप को संवारने-सुधारने में विशेष मदद करती हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बड़ी भूमिका अदा करती हैं। बानगी के रूप में कुछ नसीहतें गहरे अर्थ वाली भी हैं। मसलन, 'जीभ सुधर जाए तो जीवन सुधरने में वक्त नहीं लगता'। 'दीपक इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता।' 'जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है, वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है।' 'सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती; ना किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में।'

इन नसीहतों में जीवन के मूल्य हैं, नैतिकता के सबक और व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरणा है। अपनों को अपना बनाए रखने का चुंबक है और परायों को अपना बनाने के नुस्खे भी। नसीहत के फूल किसी को दें तो उसकी खुशबू खुद भी लेना न भूलें। सब मानते हैं कि दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। विरासत में हर बार जागीर और सोना-चांदी नहीं मिलता, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। अपना अहं त्याग कर शक्तिशाली होने पर भी सरल रहने की जरूरत है। धनी न होने पर भी परिपूर्ण महसूस करना चाहिए। हालांकि जिंदगी में सरल होना आसान है, पर देखा यह गया है कि कठिन होने को लोग सरल मानते हैं और सरल होना फिर खुद-ब-खुद कठिन हो जाता है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है।

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

अमेरिका के साथ

अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में दो शासनाध्यक्षों की मित्रता के रूप में पचास हजार दर्शकों के बीच आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम वास्तव में भारत-अमेरिका के सांस्कृतिक संबंधों की सकारात्मकता का उदाहरण है। यह अलग बात है कि अगले साल अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी वहां बसे भारतीय मूल के लोगों में वोट बैंक नजर नजर आ रहा है। अगर ऐसा है भी तो भारतीय नजरिए से गलत क्या है। ये लोग पहले से वहां बसे हैं और भारत-अमेरिका संबंध अब तक उतार-चढ़ाव के रूप में ही दिखता रहा है। यदि इन नागरिकों की बदौलत भारत अमेरिका संबंधों के विभिन्न आयामों में प्रगाढ़ता आती है तो वहां बसे लाखों भारतीय को भी अपनापन का एहसास होगा। भारतवंशी अपने देश के नेता को सुनने आए थे। ऐसे में अमेरिकी यदि भारत के प्रधानमंत्री के प्रशंसक हो जाते हैं तो भारत को इससे लाभ ही हैं। प्रधानमंत्री ने वहां आतंकवाद का मुद्दा उठाया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस मुद्दे पर भारत के साथ मिल कर काम करने का जो भरोसा दिया वह भारत के लिए बेहतर ही है। ऊर्जा के मसलों पर दोनों राष्ट्रों के मध्य हो रही साझेदारी ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए विकल्पों का बेहतर मार्ग प्रशस्त करेगा।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार*

जिम्मेदार कौन

कोलकाता का जाधवपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिरा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में जब स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें बंधक बना लिया गया। हालांकि उन्होंने इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। किंतु ऐसा करने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे या बाहरी लोग, यह जांच का विषय है। यह समझने वाली बात है कि जेएनयू जैसा दिल्ली का विश्वविद्यालय जिसमें हजारों विद्यार्थी पढ़ते है, भारत का नाम ऊंचा करते है, किंतु कुछ अतिवादी तत्वों के कारण विश्वविद्यालय बदनाम हो जाते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को कौन संरक्षण देता है? इनके रक्षा कवच को तोड़ कर ऐसे लोगों को दंडित करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के तत्व समाज में समरसता और स्नेह के वातावरण को दूषित करते हैं और शिक्षण संस्थानों को गलत दिशा में ले जा रहे है। यही कारण है कि विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों की सूची में भारत के विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत नीचे आ गया।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, धार*

गद्दारों की चिंता

आतंकी मुल्क पाकिस्तान दुनियाभर में कश्मीर मुद्दे को लेकर ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत सरकार कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है और उनके नेताओं का हुक्का-पानी बंद कर रखा है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कश्मीरियों की चिंता नहीं है, उन्हें भारत के उन गद्दारों की चिंता है जो खाते तो भारत की हैं, रहते भारत में हैं, लेकिन साथ पाकिस्तान का देते हैं और उनके कहने पर घाटी में आतंकियों को घुसने देते हैं। यही नहीं, इन आतंकियों को अपने घर में भी पनाह भी देते हैं। पाकिस्तान अलगाववादी और उन कश्मीरी नेताओं की चिंता कर रहा है, जिनके दिल में भारत नहीं पाकिस्तान और आतंकवाद बसता है। लेकिन भारत की सरकार ने उनको जेलों में ठूस दिया है, इसलिए पाकिस्तान बौखला रहा है। आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान को पूरे विश्व में मुंह की खानी पड़ रही है। रविवार को ह्यूस्टन में भी प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंच साझा कर इशारों-इशारों में पाकिस्तान को बता दिया कि अगर आतंक को संरक्षम देने का काम बंद नहीं किया तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।

● *ब्रजेश सैनी, बिंदकी फतेहपुर, उप्र*

साझा सरोकार

हाल ही में ह्यूस्टन में हुए भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशी भारतीयों ने हिस्सा लिया। जहां एक और ट्रम्प के लिए यह अमेरिका में अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की योजना का हिस्सा था दूसरी और भारत ने भी कई सन्देश इस कार्यक्रम के द्वारा पूरी दुनिया को दिए। जैसे की भारत और अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध एक साथ मजबूती से खड़े है व कश्मीर से 370 हटाने के मामले में भी अमेरिका का समर्थन है। भारत व अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे व्यापारिक तनाव को कम करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। भले ही ट्रम्प के लिए यह चुनाव प्रचार का हिस्सा हो लेकिन आज अमेरीकी-भारतीय और भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का एक महत्वपूर्ण केंद्र है इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि भारत और भारतीयों का प्रभाव व ताकत पूरी दुनिया में आश्चर्य जनक रूप से बढ़ी है और भारतीयों और भारतीय राजनेताओ में अपनी बात किसी भी स्थान पर मुखरता के साथ रखने की प्रवृति जाग्रत हुई है जो की दर्शाता है की भारत विश्वगुरु बनने के अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है।

● *सुनील कुमार सिंह, मेरठ, उप्र*

जरूरी जुर्माना

नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में दोषी वाहन चालकों पर भारी जुर्माना निर्धारित किया गया है, जो पूरी तरह से उचित है, क्योंकि बिना सख्ती के शासन चलता भी नहीं है। मगर इसमें एक बड़ी कमी यह है कि इसमें दूसरे इतने ही जिम्मेवार पक्ष को छोड़ दिया गया है जो तर्कसंगत नहीं है। इसके लिए खराब और जानलेवा सडकों, फुटपाथों,चौराहों, पुलों, अंडरपास आदि के सभी जिम्मेवार अधिकारियों, ठेकेदारों और नियोजकों आदि पर भी ऐसे ही जुर्माने बहुत जरूरी हैं ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे और यह पूरे देश में समान रूप से लागू हो सके। केंद्र के कानून तो पूरे देश के लिए बनते हैं। यदि कुछ राज्य इसे लागू करें, कुछ न करें और कुछ इसे तोड़-मरोड़ कर लागू करें, तो यह किसी के लिए भी शोभायमान नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को इसे इस जरूरी संशोधन के साथ ही लागू करना जरूरी है।

● *वेद मामूरपुर, नरेला*